

## कृषि विभाग

दिनांक 10 मार्च, 2005

**संख्या 437-कृषि-अनु(1)-2005/3616.**—पंजाब कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 (1961 का अधिनियम 23), की धारा 43 की उपधारा (2) के खण्ड (xx) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड तथा मार्केट कमेटी अधिशेष निधि निवेश तथा निपटान नियम, 1981, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. ये नियम हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड तथा मार्केट कमेटी अधिशेष निधि निवेश तथा निपटान (संशोधन) नियम, 2005, कहे जा सकते हैं।

2. हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड तथा मार्केट कमेटी अधिशेष निधि निवेश तथा निपटान नियम, 1981 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 2 में, खण्ड (ख) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(खख) ‘अध्यक्ष’ से अभिप्राय है, अध्यक्ष हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड;”।

3. उक्त नियमों में, नियम (3) में, उप-नियम (1) के बाद, निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(1-क) मार्केट कमेटी/बोर्ड की अधिशेष निधियों को, अध्यक्ष तथा मुख्य प्रशासक के पूर्व अनुमोदन से सरकार के स्वामित्वाधीन वित्तीय संस्थाओं द्वारा उन्नत निजी क्षेत्र में निम्नलिखित वाणिज्यिक बैंकों में निवेश किया जा सकता है :—

(i) इंडस्ट्रियल क्रेडिट एण्ड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन आफ इंडिया (आई० सी० आई० सी० आई० बैंक लिमिटेड)

(ii) इंडस्ट्रियल डिवेलपमेंट बैंक आफ इंडिया।

(iii) हाउसिंग डिवेलपमेंट एण्ड फाईनांस कार्पोरेशन बैंक लिमिटेड।

(iv) स्माल इंडस्ट्रीज डिवेलपमेंट बैंक आफ इंडिया।”।

के० एस० भोरिया,

वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,

कृषि विभाग।

## AGRICULTURE DEPARTMENT

The 10th March, 2005

**No. 437-Agri. S(1)-2005/3616.**—In exercise of powers conferred by Sub-section (1) read with clause (xx) of the Sub-section (2) of Section 43 of the Punjab Agricultural Produce Markets Act, 1961 (Act 23 of 1961), the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana State Agricultural Marketing Board and Market Committees Investment and Disposal of Surplus Funds Rules, 1981, namely :—

1. These rules may be called the Haryana State Agricultural Marketing Board and Market Committees Investment and Disposal of Surplus Funds (Amendment) Rules, 2005.

2. In the Haryana State Agricultural Marketing Board and Market Committees Investment and Disposal of Surplus Funds Rules, 1981 (hereinafter called the said rules), in rule 2, after clause (b), the following clause shall be inserted, namely :—

“(bb) ‘Chairman’ means the Chairman of the Haryana State Agricultural Marketing Board;”.

3. In the said rules, in rule 3, after sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely :—

“(1-A) The surplus funds of the Market Committees/Board can be invested in the following Commercial Banks in the private sector promoted by a Government owned financial institution with the prior

approval of Chairman and Chief Administrator :—

- (i) Industrial Credit and Investment Corporation of India Ltd. (ICICI Bank Ltd.)
- (ii) Industrial Development Bank of India (IDBI) Ltd.
- (iii) Housing Development and Finance Corporation (HDFC).
- (iv) Small Industries Development Bank of India (SIDBI).

K. S. BHORIA,

Financial Commissioner and Principal Secretary to  
Government Haryana, Agriculture Department.

राजस्व विभाग

आदेश

दिनांक 10 मार्च, 2005

**संख्या 868-र-3-2005/2619.**—चूंकि, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का अधिनियम 1) की धारा 6 के अधीन जारी की गई, हरियाणा सरकार, राजस्व विभाग, अधिसूचना संख्या 1645-र-3-2004/4894, दिनांक 4 मई, 2004, में विशिष्टियों में वर्णित भूमि, सरकार द्वारा, सरकारी खर्च पर, सार्वजनिक प्रयोजन अर्थात् गांव कलायत, तहसील तथा जिला कैथल में, उप तहसील, कलायत के कार्यालय भवन तथा रिहायशी मकानों के निर्माण हेतु अपेक्षित घोषित की गई है।

इसलिए, अब, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का अधिनियम 1), की धारा 7 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, जिला राजस्व अधिकारी एवं भूमि अर्जन कलक्टर, कैथल, जिला कैथल को निदेश देते हैं कि वह पूर्वोक्त अधिसूचना के साथ प्रकाशित घोषणा से संलग्न विशिष्टियों में वर्णित भूमि के अर्जन के आदेश लें।

के० सी० शर्मा,

वित्तियुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,  
राजस्व विभाग।

#### REVENUE DEPARTMENT

#### Order

The 10th March, 2005

**No. 868-R-3-2005/2619.**—Whereas, the land described in the Haryana Government, Revenue Department, Notification No. 1645-R-3-2004/4894, dated the 4th May, 2004, issued under Section 6 of the Land Acquisition Act, 1894 (Act 1 of 1894), has been declared to be needed by the Government, at public expense, for a public purpose, namely, for the construction of Sub-tahsil Kalayat office building and residential houses, in Village Kalayat, Tehsil and District Kaithal.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7 of the Land Acquisition Act, 1894 (Act 1 of 1894), the Governor of Haryana hereby directs the District Revenue Officer-cum-Land Acquisition Collector, Kaithal, District Kaithal, to take order for the acquisition of the land described in the specifications appended to the declaration published with the aforesaid notification.

K. C. SHARMA,

Financial Commissioner and Principal Secretary to  
Government Haryana, Revenue Department.